



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

No. 29]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

सं. 56 /2015–2020द्व

विषयः—षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु लंबित आवेदनों के निपटान संबंधी प्रक्रिया।

फा. सं. 01/94/180/63/एम-16/पीसी-4/721.—इस निदेशालय में व्यापार एवं उद्योग और डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों से जहां डीएफआईए को जारी किया जाना है, ऐसे लंबित आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने तथा जहां डीएफआईए पहले ही जारी किया जा चुका है उनके हस्तांतरण हेतु आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने की प्रणाली के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं। अतः विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा डीएफआईए को जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं :

- निर्यात पूर्व डीएफआईए तथा वास्तविक प्रयोगकर्ता घर्त तथा निर्यात पूरा होने के उपरांत इनके हस्तांतरण का उल्लेख विदेश व्यापार नीति 2009–14 में किया गया था। विभिन्न षुल्कों से छूट प्रदान करने का उल्लेख विदेश व्यापार नीति 2009–14 के साथ पठित पैरा 4.2.6 के घट एवं (घ.) में किया गया था। विदेश व्यापार नीति 2015–20 में दिनांक 01.04.2015 से षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) और वास्तविक प्रयोगकर्ता (एयू) की घर्त को हटा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.2.6 के अनुसार अब डीएफआईए स्कीम केवल पञ्च निर्यात आधार पर मूल सीमा षुल्क से ही पात्र छूट देने हेतु उपलब्ध है।

- प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.28 (प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 का संदर्भित पैरा 4.12.1) के अनुसार “अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने से पूर्व किए गए निर्यात/आपूर्ति का जोखिम और जिम्मेदारी पूरी तरह निर्यातक की होगी।”

इसके अतिरिक्त, यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यातक को षुल्क वापसी अनुमत करने संबंधी अग्रिम प्राधिकार पत्र का आवेदन, यदि ग्राह्य हो, निरस्त अथवा स्वीकृत कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.29 (प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 का संबद्ध पैरा 4.12.2) के तहत निर्यातक को षुल्क मुक्त पोतलदान बिलों को षुल्क वापसी पोतलदान बिलों में परिवर्तित करने का भी विकल्प दिया गया है।

- अधिसूचना सं. 5/2015–20 दिनांक 01.05.2015 के तहत षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम के अंतर्गत “खांड” के आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। अतः दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके पश्चात “खांड” के आयात हेतु जारी डीएफआईए पर डीएफआईए स्कीम का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

4. डीएफआईए जारी करने तथा इसके हस्तांतरण हेतु किए गए अनुरोधों का निपटान निम्नलिखित पैराग्राफ के अनुसार किया जाएगा:
- 4.1 वे मामले जिनमें 01.04.2015 तक प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी नहीं किया जा सका:
- क. उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01.04.2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था परन्तु निर्यातकों द्वारा 01.04.2015 से पहले कोई निर्यात नहीं किया गया था— ऐसी परिस्थितियों में, आवेदन पत्र को वैध आवेदन पत्र के रूप में माना जाएगा और क्षेत्रीय प्राधिकरण एफटीपी 2015–20 और एचबीपी 2015–20 के अनुसार पञ्च निर्यात के आधार पर डीएफआईए जारी कर सकता है।
- ख. उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01.04.2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 31.03.2015 तक निर्यात आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से किए गए थे—ऐसी परिस्थितियों में, क्षेत्रीय प्राधिकरण केवल एफटीपी 2015–20 और एचबीपी 2015–20 के अनुसार पञ्च निर्यात के आधार पर ग्राह्यता के अनुसार डीएफआईए जारी कर सकता है।
- ग. उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01.05.2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 30.04.2015 तक निर्यात आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से किए गए थे—ऐसी परिस्थितियों में, और जहां निर्यातक ने सिझॉन के अनुसार “खांड” को निविष्टि के रूप में प्रयोग किया है—ऐसी परिस्थितियों में, डीएफआईए निर्यात खेपों पर ‘खांड’ की हकदारी की सीमा तक अनुमत होगा जिस पर अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) 30.04.2015, गुरुवार को रात्रि 12:00 बजे तक जारी किए गए हैं। 01.05.2015 को अथवा बाद में अनुमत निर्यात आदेष वाला कोई पोतलदान जहां पर ‘खांड’ को एक निविष्टि के रूप में प्रयोग किया गया है, को डीएफआईए का पात्र नहीं माना जाएगा। निर्यातकों के पास एचबीपी 2015–20 के पैरा 4.29 के अनुसार पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प रहेगा।
- 4.2 ऐसे मामले जिनमें शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (जिनमें निविष्टि के रूप में खांड का आयात शामिल नहीं है) विदेष व्यापार नीति 2009–14 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे परन्तु हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर दिनांक 30.03.2015 तक विचार नहीं किया जा सका।
ऐसे मामलों में हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेष व्यापार नीति 2009–14 के दौरान जारी शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्रों (डीएफआईए) के नियम एवं षट्ठी के अनुसार विचार किया जा सकता है, बष्ठर्ते सभी दस्तावेज क्रम में हों।
- 4.3 खांड के आयात के ऐसे मामले जिनमें हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका।
- क. शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जो कि पूर्ववर्ती विदेष व्यापार नीति 2009–14 के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके थे और इनमें निविष्टि के रूप में खांड को शामिल किया गया था, के संबंध में हस्तांतरण हेतु अनुरोध— विदेष व्यापार नीति 2009–14 के अनुसार डीएफआईए के ऐसे मामलों में हस्तांतरण के अनुरोधों पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी निर्यात खेपों जिनके लिए बृहस्पतिवार 30.04.2015 को 12:00 बजे रात्रि तक अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) जारी किए गए हैं, के लिए खांड की पात्रता की अनुमति देकर विचार किया जा सकता है। दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके बाद अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) के साथ किया जाने वाला निर्यात अधिसूचना सं. 5 / 2015–20 को देखते हुए डीएफआईए लाभ का पात्र नहीं होगा। निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.29 के अनुसार अपने पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- ख. विदेष व्यापार नीति 2015–20 के अनुसार दिनांक 01.04.2015 से 30.04.2015 तक किए गए निर्यात जिसमें खांड निविष्टि है, के संबंध में हस्तांतरणीय डीएफआईए हेतु अनुरोध— विदेष व्यापार नीति 2015–20 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी दिनांक 01.04.2015 से 30.04.2015 तक भेजी गई निर्यात खेपों, जिनके लिए बृहस्पतिवार 30.04.2015 को 12:00 बजे रात्रि तक अनुमत निर्यात आदेष जारी किए गए हैं, हेतु खांड की पात्रता अनुमत करके हस्तांतरणीय डीएफआईए प्रदान कर सकता है। दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके बाद अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) के साथ किया जाने वाला कोई भी निर्यात अधिसूचना सं. 5 / 2015–20 को देखते हुए डीएफआईए लाभ का पात्र नहीं होगा। निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.29 के अनुसार अपने पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प होगा।
5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: डीएफआईए जारी करने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकरण में लम्बित आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने हेतु कार्यप्रणाली जारी की गई है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd January, 2016

No. 56 /2015-2020

Subject: Procedure to deal with the pending applications for issuance of Duty Free Import Authorisation(s) (DFIA) and their transferability.

F. No. 01/94/180/63/AM 16/PC4/721.—Several references have been received in this Directorate from Trade and Industry and Regional Authorities of DGFT regarding the manner of processing pending applications where DFIA are yet to be issued and the manner of processing applications for transferability where DFIA have already been issued. Therefore, *in exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies procedure to be followed for issuance of DFIA and their transferability as under:*

1. Pre-Export DFIA with AU condition and subsequent transferability on completion of export was available in the FTP 2009-14. Exemption from various duties was available as per Para 4.2.2 (d)&(e) read with para 4.2.6 of FTP2009-14. In [FTP 2015-20](#) the Duty Free import Authorisation (DFIA) with AU condition has been dispensed with w.e.f 1.04.2015. Now DFIA scheme is available only on Post Export basis with eligible exemption only from basic customs duty as per para 4.26 of [FTP 2015-20](#).
2. As per Para 4.28 of HBP 2015-20 (relevant Para 4.12.1 of HBP 2009-14) “Exports/supplies made in anticipation of grant of Advance Authorisation shall be entirely on risk and responsibility of the exporter.” Moreover, the exporter has also been given the option under Para 4.29 of HBP 2015-20 (relevant para 4.12.2 of HBP 2009-14) to get conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills in case application of Advance Authorisation is rejected or modified by RA for allowing drawback to the exporter, if admissible.
3. Vide Notification No. 5/2015-20 dated 1.05.2015, import of “raw sugar” under Duty Free Import Authorization (DFIA) scheme was withdrawn with immediate effect. Therefore, no benefit of DFIA scheme can be allowed for import of “raw sugar” on DFIA issued on or after 1.05.2015.
4. The manner of dealing with the requests for issuance of DFIA and transferability will be as per paragraphs given below:
 - 4.1 **Cases where Authorisation (DFIA) could not be issued up to 1.04.2015:**
 - a. **Cases where DFIA applications were filed on line to Regional Authorities (RAs) before 1.04.2015 by exporters but no exports have been made by exporter before 1.04.2015-** In such situations, application will be treated as valid application and RA may issue DFIA based on Post Export basis only as per [FTP 2015-20](#) and HBP 2015-20.
 - b. **Cases where DFIA applications were filed on line to Regional Authorities (RAs) before 1.04.2015 by exporters and exports have been made partially/fully up to 31.03.2015-** In such situation, RA may issue DFIA based on Post Export basis only as per [FTP 2015-20](#) and HBP 2015-20 as per admissibility.
 - c. **Cases where DFIA applications were filed on line to Regional Authorities (RAs) before 1.05.2015 by exporters and exports have been made partially/fully up to 30.04.2015 and exporter has used “raw sugar” as input as per SION-** In such situations, DFIA will be allowed as per [FTP 2015-20](#) to the extent of the entitlement of “raw sugar” on the export consignments for which Let Export Orders (LEOs) have been issued till 2400 hrs on Thursday 30.4.2015. Any shipments having LEO on or after 1.05.2015, where raw sugar has been used as an input will not be eligible for grant of DFIA. Exporter will have option to avail facility to get his Shipping Bills converted to Drawback Scheme as per para 4.29 of HBP 2015-20

4.2 Cases where DFIA (not involving import of raw sugar as an input) was issued as per provisions of [FTP 2009-14](#) but request for transferability could not be considered up to 30.03.2015.

In such cases Transferability request may be considered by RA as per the terms and conditions of DFIA issued during FTP 2009-14, provided all documents are in order.

4.3 Cases involving import of raw sugar where request for transferability could not be considered.

- a. **Request for transferability in respect of DFIA which were already issued in earlier [FTP 2009-14](#) and involve raw sugar as an input** – Requests of transferability in such cases of DFIAAs may be considered by RA, as per [FTP 2009-14](#), by allowing entitlement of raw sugar for export consignments for which Let Export Orders (LEOs) have been issued till 2400 hrs on Thursday 30.4.2015. Any exports with LEO on or after 1.05.2015 will not be eligible for DFIA benefit in view of Notification No. 5/2015-20. Exporter will have option to avail facility to get his Shipping Bills converted to Drawback Scheme as per para 4.29 of HBP 2015-20.
 - b. **Requests for transferable DFIA as per [FTP 2015-2015](#) on the exports made from 1.04.2015 till 30.04.2015 where raw sugar in an input**– RA may grant transferable DFIA as per [FTP 2015-2015](#) by allowing entitlement of raw sugar for export consignments made from 1.04.2015 up to 30.04.205 for which Let Export Orders (LEOs) have been issued till 2400 hrs on Thursday 30.4.2015. Any exports with LEO on or after 1.05.2015 will not be eligible for grant of DFIA benefit in view of Notification No. 5/2015-20. Exporter will have option to avail facility to get his Shipping Bills converted to Drawback Scheme as per para 4.29 of HBP 2015-20.
5. **Effects of this Public Notice:** Procedure for processing pending applications in RA for issuance and transferability of DFIAAs has been issued.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade